एडीसी द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों की समीक्षा: एक और सरकारी नाटक

एडीसी अपराजिता, आईएएस

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) 'काम नहीं करना, काम करने का ढोल जरूर पीटना' यही है खट्टर सरकार की घोषित नीति। इसी नीति पर अमल करते हुए तमाम सरकारी अधिकारी सरकार को सुर्खियों में बनाये रखने के लिये काम करने के बजाय, काम करने का केवल ढोल पीटते रहते हैं। इसी नीति का अनुसरण करते हुए एडीसी अपराजिता ने भी सड़क सुरक्षा नियमों की समीक्षा करते हुए अपने कर्त्तव्य की यह कहते हुए इतिश्री कर ली कि सड़क सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जाए।

इस तरह की समीक्षायें एवं दिशा निर्देश तमाम आते-जाते प्रशासनिक अधिकारी करते रहते हैं जिनका धरातल पर कोई पालन होता नज़र नहीं आता। समझ नहीं आता कि प्रशासनिक अधिकारी उक्त दिशा निर्देशों का पालन करने की अपेक्षा किससे करते हैं? सर्वविदित है कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने के लिये सबसे बड़े दोषी सरकारी विभाग-नगर निगम, 'हूडा', पीडब्लूडी, बिजली विभाग आदि हैं। आए दिन होने वाली गम्भीर एवं घातक दुर्घटनाएं इन्हीं विभागों की हरामखोरी एवं लापरवाही के चलते होती है, लेकिन इसके बावजूद आज तक इसके लिये कोई अधिकारी जेल नहीं भेजा गया। यदि कोई एक अधिकारी को भी जिम्मेदार ठहरा कर जेल भेज दिया गया होता तो सड़क दुर्घटनाएं बंद नहीं तो कम जरूर हो जातीं।

पुलिस विभाग का तो कहना ही क्या, सड़क पर बने गड्ढों में गिरे दुपहिया चालक को यदि पीछे से आने वाला ट्रक रौंद दे तो दोषी ट्रक ड्राइवर को ठहराया जाता है न कि सड़क पर गड्ढों व उनमें भरे पानी तथा अंधेरे के लिये जिम्मेदार अधिकारियों को। वाहनों के चलने के लिये बनी सड़क पर खड़े रहते वाहनों को देख कर पुलिस अनदेखा कर देती है। वाहन चेकिंग का मतलब केवल वसूली मात्र रह गया है।

पैदल व साइकिल चालक अपनी जान हथेली पर लेकर सड़कों पर निकलते हैं। इन लोगों के लिये अलग से कोई ट्रैक धरातल पर तो नहीं बनाये गये हैं, हां, फाइलों में जरूर बने हुए हैं। ऐसा ही एक ट्रैक करीब चार साल पूर्व बाटा मोड़ से कचहरी जाने वाली सड़क पर बनाकर 18 लाख डकार लिये गये थे, आज वह ट्रैक ढूंढने से भी नहीं मिलता।

अतिरिक्त मोटी रकम डकारने के लिये इसी सड़क पर फ़िर से ट्रैक बनाने का खेल खेला जा रहा है। ऐसे में एडीसी महोदया इन पैदल चलने व साइकिल चालकों से कौन से दिशा निर्देशों के पालन की अपेक्षा करती हैं?

निगम के नकली इंजीनियरों का कारनामा

सैनिक कॉलोनी में सीवर लाइन डालने के नाम पर बर्बाद किए करोड़ों रुपये

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) फर्जी डिग्री लेकर नगर निगम में इंजीनियर पद हासिल करने वाले अफसरों ने सैनिक कॉलोनी में सीवर लाइन पर करोड़ों रुपये बर्बाद कर दिए। यहां डिस्पोजल को जोड़ने वाली लाइन सीवर लाइन से साढ़े पांच फीट ऊंचाई पर डाल दी गई। अनपढ़ इंजीनियरों द्वारा काम पर लगाया गया ठेकेदार उनसे भी बड़ा अनपढ़ निकला। उसने गलत होने के बावजूद लाइन डाल दी और भुगतान लेकर चलता बना।

सैनिक कॉलोनी में रहने वाले करीब पांच हजार परिवारों की सीवर जाम की समस्या समाप्त करने के लिए नगर निगम ने करोड़ों का प्रोजेक्ट तैयार किया था। इसके तहत सैनिक कॉलोनी के घरों से निकलने वाली ब्रांच सीवरेज लाइन को डिस्पोजल तक ले जाने वाली मेन लाइन से जोड़ा जाना था। कांलोनी में ब्रांच लाइन जमीन से 17 फीट नीचे डाली गई है। ब्रांच लाइन से सीवरेज डिस्पोजल तक ले जाने वाली लाइन इस लाइन से एक या दो फीट अधिक गहराई में डाली जानी चाहिए थी। निगम में बैठे नकली इंजीनियरों ने आनन-फानन लाइन बिछाने की डीपीआर तैयार कर डाली। भौतिक विज्ञान के मूल नियमों से भी अनजान इन इंजीनियरों ने डीपीआर में गुरुत्वाकर्षण बल की भी धज्जियां उड़ा दीं। 17 फीट गहरी सीवर लाइन के लिए 11.5 फीट यानी साढ़े पांच फीट ऊपर डिस्पोजल फीडिंग लाइन बिछाने का प्रोजेक्ट बना डाला। इन अधपढ़े इंजीनियरों की करतूत निगम के बड़े और काबिल अधिकारियों ने भी नहीं देखी और ठेका जारी कर दिया गया।

यह टेंडर यदि किसी योग्य ठेकेदार को मिलता तो वह इतनी बड़ी गलती से निगम अधिकारियों को अवगत कराता लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों की तवज्जो काम पर नहीं कमीशन हासिल करने की होती है। जाहिर है कि चालीस से पचास प्रतिशत कमीशन बांटने वाले ठेकेदार उल्टा सीधा काम ही करेंगे।

निगम के भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक लाइन बिछाने में गड़बड़ी इंजीनियरों और ठेकेदार की मिलीभगत से ही की गई थी। यदि साढ़े ग्यारह फीट पर डाली गई लाइन की गुणवत्ता जांची जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। फीडरलाइन फेल होने पर कुछ समय बाद इसे दोबारा डालने का खेल किया जाएगा और फिर कमीशनबाजी होगी। कर के रूप में जनता से वसूली गई उसके गाढ़े पसीने की कमाई भ्रष्ट निगम अधिकारी इसी तरह लूट खसोट करते रहेंगे। निगम आयुक्त जीतेंद्र दहिया ने बताया कि सैनिक कॉलोनी में फीडिंग सीवर लाइन गलत डाले जाने की बात उनकी जानकारी में आई है। लोगों को सुविधा दिलाने के लिए सही फीडिंग लाइन डलवाई जाएगी।

सवाल यह पैदा होता है कि गलत लाइन डाले जाने का हर्जाना कौन भुगतेगा, कमिश्नर ने यह नहीं बताया कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है और हर्जाना कौन भुगतेगा।

बिना सिपहसलार कामयाबी से दूर होती जा रही कांग्रेस

– बीते आठ साल से कांग्रेस जिला कमेटियां हैं भंग

– प्रदेश स्तर पर बड़े पदाधिकारियों की गुटबंदी से हो रही अधोगति

हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) 2024 में केंद्र और राज्य के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं लेकिन कांग्रेस अभी तक अपने सिपहसलार यानी कि जिला स्तरीय कमेटियों के पदाधिकारी भी तैनात नहीं कर सकी है। पांच से दस वोटरों पर एक पदाधिकारी तैनात करने के इस युग में बिना संगठन के चुनाव जीतना कांग्रेस के लिए असाध्य लक्ष्य होगा।

हरियाणा में तीन दशक से ज्यादा समय तक राज करने वाली कांग्रेस पार्टी को 2014 में भाजपा ने सत्ता से बाहर कर दिया। सत्ता से बेदखल होने के साथ ही पार्टी में जिला स्तर पर पद हासिल करने के लिए उठापटक शुरू हुई तो सभी जिला कमेटियां भंग कर दी गईं। कांग्रेस के प्रदेश स्तर पर सैलजा, अशोक तंवर (जो अब पार्टी छोड़ चुके हैं) और भूपेंद्र हुड्डा के बीच सत्ता की खींचतान का असर यह हुआ कि जिला स्तर की कमेटियों के गठन की ओर जानबूझ कर ध्यान नहीं दिया गया। संगठन नहीं होने के कारण बीते आठ साल में अनेक कांग्रेसी हतोत्साहित होकर पार्टी की गतिविधियों से किनारा कर चुके हैं या किसी अन्य पार्टी का दामन थाम चुके हैं। संगठनहीन होने के कारण प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस और आम जनता के बीच संवादहीनता की स्थिति है।

इसके विपरीत कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को अपना कर भाजपा ने आम जनता के बीच अच्छी पैठ बना ली है। जहां लोगों को ढूंढने पर भी कोई कांग्रेसी नहीं मिलता वहीं भाजपा कार्यकर्ता सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने, कार्ड बनवाने या कोई भी सुविधा दिलाने के नाम पर आम जनता से जुड़ते जा रहे हैं। यहां तक कि दस वोटरों पर एक पन्ना प्रमुख जैसे सूक्ष्म कार्यकर्ता तक भाजपा ने तैनात किए हैं। इन पन्ना प्रमुखों का काम उनके पन्ने पर दर्ज दस वोटरों से भाजपा के पक्ष में वोट डलवाना है।

यह भी समझना जरूरी है कि कांग्रेसी जहां वोटर लिस्ट में नए मतदाता का नाम जुड़वाने का प्रयास नहीं कर रहे वहीं सत्ता पक्ष के कार्यकर्ता ऐसे मतदाताओं के नाम आपत्ति लगा कर मतदाता सूची से हटवाने में सक्रिय हैं जो उनकी पार्टी के खिलाफ वोट डाल सकते हैं। तीन दशक से भी अधिक समय तक सत्ता भोगने वाले कांग्रेसी अभी भी इस घमंड में हैं कि जनता उन्हें खुद ही वोट देगी। उनका यह मुगालता 2024 के चुनावों में पार्टी को भारी पड़ सकता है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।